राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 96वीं एवं 97वीं संयुक्त बैठक

96th & 97th JOINT MEETING OF STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE, BIHAR

* *

23 जून, 2026 11:00 पूर्वाह्न **23 JUNE, 2026 11:00 AM**

कार्यसूची (AGENDA)

1. राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की दिनांक 22.01.2026 को हुये 95वीं त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त का अंगीकरण।
   (Adoption of the minutes of 95th quarterly meeting of SLBC, Bihar held on 22.01.2026)

2. राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार की 95वीं त्रैमासिक बैठक के कार्यबिन्दुओं पर चर्चा।
   (Deliberations on the Action Points of the 95th quarterly meeting of SLBC, Bihar)

3. वित्तीय समावेशन पहल, बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार, व्यापार संवाददाताओं का संचालन और वित्तीय साक्षरता की समीक्षा। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (NSFI): 2025-30।
   (Review of financial inclusion initiatives, expansion of banking network, operation of Business Correspondents (BCs) and Financial Literacy. National Strategy for Financial Inclusion (NSFI): 2025-30)

i) सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Social Security Schemes): प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY)

ii) प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं अन्य खातों में पुनः केवाईसी।
   (Re-KYC in PMJDY & Other Accounts)

iii) बैंकिंग छेत्र में अनक्लेमेड ऐसेट्स के सुगम और त्वरित निपटान।
   (Efficient and quick settlement of unclaimed assets in the banking sector)

iv) बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की स्थिति, बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस सक्षम बैंकिंग आउटलेट।
   Status of opening of banking outlets in unbanked villages, CBS-enabled banking outlets at the unbanked rural centres) (URCs)

v) राज्य में भुगतान के डिजिटल तरीकों को बढ़ाने की दिशा में प्रगति, जिलों में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनीकरण- संपोषण, ATM व POS मशीन की उपलब्धता।
   (Progress in increasing digital modes of payment in State Expanding and Deepening of Digital Payments Ecosystem - Sustenance, installation of ATMs and PoS machines)

vi) आधार सीडिंग व प्रमाणीकरण की स्थिति, डीबीटी लाभार्थियों के **Inoperative/ Frozen** खातों के पुनर्परीचालित और केवाईसी संबन्धित मुद्दे।
(Status of Aadhar seeding and authentication, Resolution of issues related to KYC / Re-KYC and reactivating inoperative / frozen accounts to avail DBT benefits)

4. बैंकों के द्वारा ऋण वितरण की समीक्षा।
(Review of credit disbursement by Banks)

(i) वार्षिक साख योजना 2025-26 के अंतर्गत उपलब्धि।
(Achievement under ACP 2025-26)

ii) एम० एस० एम० ई० क्षेत्र को वित्त पोषण।
(Flow of credit to MSMEs)

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पी० एम० एफ़० एम० ई०, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पी० एम० स्वनिधि, पी० एम० विश्वकर्मा योजना, पी० एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आदि सरकार समर्थित योजनाओं के अंतर्गत समीक्षा।
(Discussion on lending towards Government Sponsored Schemes (PMEGP, PMFME, PMMY, PM-SVANidhi, PMVY, PMSGMBY)

iv) वार्षिक साख योजना 2026-27 के लक्ष्यों पर चर्चा।
(Discussion on ACP target 2025-26)

v) कृषि (Agriculture) –

(अ) के०सी०सी० फसल ऋण (KCC Crop Loan),
(आ) कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund)
(ई) भारत सरकार के जनसमर्थ पोर्टल से के०सी०सी० की शुरुआत.
(Onboarding of KCC to JanSamarth portal of Government of India)

vi) पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन (Animal Husbandry & Fisheries): -- a) के०सी०सी० – पशुपालन (KCC–Animal Husbandry), b) के०सी०सी० – मत्स्य (KCC – Fisheries), c) पशुपालन में अन्य ऋण (Other loans under Animal Husbandry)

vii) स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)

(अ) स्वयं सहायता समूह के बैंक लिंकेज की प्रगति (Progress under SHG-Bank linkage)
(आ) स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को व्यतिगत वित्तपोषन (Individual financing to women linked with Self Help Group)

5. साख – जमा अनुपात (CD Ratio)

6. अनर्जक आस्तियाँ (Non-Performing Assets)

(i) बैंकों की अनर्जक आस्तियाँ (NPAs of Banks)
(ii) निलाम - पत्र वाद (Certificate Cases)

(iii) सरफेसी अधिनियम से जुड़े मामले (Cases related to SARFAESI Act.)

7. केंद्र/ राज्य सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पहल पर चर्चा (औद्योगिक नीति, एमएसएमई नीति, कृषि नीति, स्टार्ट-अप नीति, आदि) और बैंकों की अपेक्षित भागीदारी।
(Discussion on policy initiative of the Central / State Government / RBI (Industrial Policy, MSME Policy, Agriculture Policy, Start -Up Policy, etc.) and expected involvement of banks)

8. ग्रामीण आधारभूत संरचना / ऋण अवशोषण क्षमता के विकास पर चर्चा।
(Discussion on improving rural infrastructure / credit absorption capacity)

i) साख – जमा अनुपात में सुधार लाने में मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कोई भी बड़ी परियोजना।
(Any large projects conceived by the State Government to help improve CD Ratio)

ii) राज्य-विशिष्ट संभावित विकास क्षेत्रों के दायरे और भागीदार बैंकों को चुनने पर चर्चा।
(Explore the scope of state-specific potential growth areas and the way forward choosing partner banks)

iii) ग्रामीण और कृषि बुनियादी ढांचे में अंतराल की पहचान, जिसके लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है।
(Identification of gaps in rural and agriculture infrastructure, which need financing)

9. भूमि रिकॉर्ड में सुधार, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में प्रगति और निर्बाध ऋण वितरण के लिए उठाए गए कदम।
(Steps taken for improving land records, progress in digitization of land record and seamless loan disbursements)

10. बाज़ार आसूचना पर चर्चा (Discussion on Market Intelligence Issues) e.g.:

(i) जनता से जमाराशि मांगने वाली अनिगमित निकायों/फर्मों/कंपनियों की पोंजी योजनाएं/अवैध गतिविधियां।
(Ponzi Schemes / illegal Activities of Unincorporated Bodies / Firms / Companies Soliciting Deposits from the Public.)

(ii) बैंकिंग से संबंधित साइबर धोखाधड़ी, फ़िशिंग, आदि।
(Banking Related Cyber Frauds, phishing, etc.)

(iii) क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा सूदखोरी गतिविधियों के उदाहरण, अत्यधिक ऋणग्रस्तता के मामले।
(Instances of usurious activities by lending entities in the area, cases of over indebtedness,)

11. विविध (Miscellaneous)

i) ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजना।
(Credit Guarantee Scheme for e-NWR based pledge financing) (CGS -NPF)

ii) व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन
(Incentivizing Trade and Export Promotion)

12. विभिन्न विभागों / बैंकों के मुद्दे / समिति द्वारा उचित समझी गई कोई भी विषय वस्तु – अध्यक्ष की अनुमति से।

(Issues of different departments / banks /Any other issue considered suitable by the Committee–with the permission of the Chair)

=0=0=0=0=0=